control measures, implying a cut in the advance release of States' share in Central taxes during the current financial year;

(b) if so, what is the quantum of advance funds likely to be cut, State-wise;

(c) what is the extent to which it will reduce the fiscal deficit; and

(d) what other measures are proposed in the post budget era to impose a strict control on the Central expenditure?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SHANTARAM POTDUKHE): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

(d) Strict control on Government expenditure is a continuous exercise and instructions in this regard are issued to all the Ministries/Departments of the Governments of India from time to time. Recently the Government of India have taken some initiatives to reduce Government spending by way of reduction in the number of posts, reduction in travel expenditure by Government employees and by way of reduction of telephones on Government account.

Golden Angle Scheme to Improve Tourism

*215. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to start a golden angle scheme for connecting several places to improve tourism; and

(b) if so, by when this scheme is likely to be implemented?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) and (b) There is no such proposal under the consideration of the Government. However, in order to further develop the tourism sector, 15 circuits and areas have been identified for intensive development.

For this purpose, surveys have been commissioned to assess the infrastructural requirements at these places.

Closure of Badarpur Thermal Power Statio

*216. SHRI SARADA MOHANTY:

SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of POWER AND NON CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Badarpur Thermal Power Station is on the verge of closure as it has no money to buy coal;

(b) if so, what are the factors leading to such a situation; and

(c) what measures are being contemplated by Government to ensure the smooth running of this major power house?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (c) Badarpur Thermal Power Station (BTPS) is facing problems in meeting its operational expenditure, including payments for coal supplies, railway freight etc. due to the inability of the Delhi Electric Supply Undertaking (DESU) to make payments for the purchase of power from BTPS. Delhi Administration/DESU have been requested to mobilise necessary resources and make payments to BTPS for its smooth operation.

ओखला, दिल्ली में स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर

*217. **मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओखला और इसके आसपास दिल्ली में कितने स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर हैं;

(ख) क्या यह सच है कि ओखला गांव और इसके आसपास स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या अपर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) (क) ओखला टेलीफोन एक्सचेंज

द्वारा सेवित क्षेत्र में 224 स्थानीय सार्वजनिक टेलीफोन घर हैं।

(ख) और (ग) ओखला गांव और उसके निकटतम पड़ौसी गांवों में 5 सार्वजनिक टेलीफोन घर कार्यरत हैं जो फिलहाल पर्याप्त है। इस क्षेत्र में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शीघ्र ही दो और सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने का प्रस्ताव है।

फ्रेंचाइज योजना के अंतर्गत स्थानीय, एस टी डी/आई एस डी युक्त सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने की नीति को उदार बनाया गया है। इनके लिए प्राप्त आवेदन-पत्र, तकनीकी व्यवहार्यता और विभागीय औपचारिकताओं की पूर्ति के अध्यधीन उदारता से मंजूर किए जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्ट

*218. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्टों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन ओवरड्राफ्टों की वसूली के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री शान्ता राम पोट वुखे :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ राज्यों के ओवरड्राफ्ट के बारे में नवीनतम उपलब्ध सूचना निम्नानुसार है :–

(करोड़ रु० में)

राज्य	9-5-1992 की स्थिति के अनुसार ओवरड्राफ्ट की राशि
1. असम	22.49 (तीसरे दिन)
2. गुजरात	126.23 (छठे दिन)
3. हिमाचल प्रदेश	15.42 (पांचवें दिन)
4. केरल	98.79 (पांचवें दिन)
5. मध्य प्रदेश	108.97 (पांचवें दिन)
6. मणिपुर	2.87 (दूसरे दिन)
7. मिजोरम	0.53 (पहले दिन)
8. उड़ीसा	9.68 (दूसरे दिन)
9 त्रिपुरा	12.12 (छठे दिन)
10 पश्चिम बंगाल	3.68 (दूसरे दिन)

(ख) और (ग) यह राज्य सरकारों का काम है कि वे ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम में निर्धारित किए गए अनुसार अपने ओवरड्राफ्ट सात क्रमिक कार्य दिवसों की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करने हेतु कदम उठाएं।

भारत में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए विदेशी संस्थानों को सहायता

*219. **सरदार जगजीत सिंह अरीड़ा :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या विद्युत और गैर-पारस्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी संस्थानों को देश की विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए भारतीय वित्तीय संस्थाओं से 40 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी;